भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3394

जिसका उत्तर 20.03.2025 को दिया जाना है

उपग्रह आधारित राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली

3394. श्री सुधीर गुप्ता:
श्री चव्हाण रविन्द्र वसंतराव:
श्री धैर्यशील संभाजीराव माणे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपग्रह आधारित राजमार्ग टोल संग्रह प्रणाली की अपनी महत्वाकांक्षी योजना को स्थगित करने का निर्णय लिया है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या नेविगेशन विद इंडियन कांस्टेलेशन (नाविक), जिसे भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (आईआरएनएसएस) के रूप में भी जाना जाता है, अमेरिकी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) का एक भारतीय विकल्प है और जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों तथा एक्सप्रेसवे पर बिना रुके यात्रा सुनिश्चित करने एवं टोल प्लाजा को प्रतिस्थापित करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, पूरी तरह से शुरू हो गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका कब तक पूरी तरह से शुरू होना अपेक्षित है; और

(घ) क्या सरकार ने किसी ऐसे खंड की पहचान की है, जिस पर प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में बाधा-मुक्त टोल प्रणाली लागू की जाएगी, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) उद्योग और शिक्षा जगत के विशेषज्ञों वाली शीर्ष समिति और उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति ने सुरक्षा और गोपनीयता के विचारों तथा समग्र परिचालन नियंत्रण के मद्देनजर उपग्रह आधारित टोलिंग के लिए आगे विचार-विमर्श की सिफारिश की है।

विशेषज्ञ समिति द्वारा कई बैठकें की गई हैं और विचार-विमर्श के अनुसार, एएनपीआर फास्टैग सिस्टम (एएफएस) आधारित बैरियर लेस फ्री फ्लो टोलिंग के लिए कॉरिडोर/खंड आधारित परियोजनाओं के साथ आगे बढ़ने का प्रस्ताव है।

(ख) से (ग) नेविगेशन विथ इंडियन कॉन्स्टेलशन (नाविक) के साथ मौजूदा विशेषताओं के साथ, उपग्रह आधारित टोलिंग के लिए वांछित स्तर की स्थिति सटीकता प्राप्त करने के साथ-साथ उपग्रह सिग्नल प्राप्त करने के लिए उपयुक्त रिसीवर के विकास के लिए अतिरिक्त उपग्रह कॉन्स्टेलशन की आवश्यकता होती है। सैटेलाइट आधारित टोलिंग की दिशा में आगे बढ़ने के लिए और विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

(घ) "घरौंदा, चोर्यासी, निमिली, यूईआर-II और द्वारका एक्सप्रेसवे" के शुल्क प्लाजा पर बाधा मुक्त टोलिंग प्रणाली को लागू करने के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) आमंत्रित/आमंत्रित किया गया है, इन परियोजनाओं पर कार्यान्वयन के परिणामों और प्रभावशीलता के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अन्य शुल्क प्लाजा पर इसे लागू करने की संभावना है।

******